

# CSIR in Media



News Bulletin  
16<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> September 2019





CSIR-CBRI

20<sup>th</sup> September, 2019

# उचित तैयारी हो तो आपदा से नुकसान में आ सकती है कमी

• जिज्ञासा विद्यार्थी  
वैज्ञानिक संयोजन  
कार्यक्रम का आयोजन

आलेख रजिषावर सेव

रुड़की। केंद्रीय अणु अनुसंधान संस्थान में जिज्ञासा विद्यार्थी वैज्ञानिक संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को उत्तराखंड राज्य के 27 केंद्रीय विद्यालयों से आए विद्यार्थियों के लिए एक विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं जिज्ञासा कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनुपल कुमार अग्रवाल ने 'जिज्ञासा देशहित में आपदा न्यूनीकरण हेतु सीवीआरआई का योगदान' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।



विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राएं।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त उच्च शक्ति आर्शिक क्षेत्र के अंतर्गत आता

है। 1991 में उत्तराखंडी भूकंप, 1998 में मालवा भूस्खलन, 1999 में चमोली भूकंप, 2013 में केदारनाथ आपदा आदि उत्तराखंड

के सबसे भयावह आपदाओं में से थीं, जिन्होंने जनता में ज़रि ज़रि की दिव्यता उत्पन्न कर दी थी। 2010 में आंध्र भूस्खलन के कारण

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तराखंडी में लोगों की जान और माल की बहुत क्षति हुई थी। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्राकृतिक

आपदा को रोकना असंभव है, परन्तु उचित तैयारी और प्रतिक्रिया से इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के 27 केंद्रीय विद्यालयों से लोहाघट, काशीपुर, एकआरआई, ओएनएफ, मंसूरी, बनबला कैट, आईआईपी, गौनर, ओएनजीसी, कुर्ग एक व दो हाथी बड़कला, ओएफडी, रुड़की, आईएमए, अमरसुनि, आईटीवीए फाली एक व दो, अपर कैप देहरादून, वीरपुर, आधिकार, राखवाल, पीटी, उत्तराखंडी, सीएचईएल हरिद्वार तथा हरद्वानी फाली एक व दो-से लगभग 200 विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों संग प्रतिभागिता की।

इस अवसर पर डॉ. आर धर्मलु, एचके जैन, किशोर कुलकर्णी, अशीष पिप्ल, श्रीनिवास, हिमांशु शर्मा आदि मौजूद रहे।

Published in:  
Dainik Bhaskar



CSIR-IMMT

20<sup>th</sup> September, 2019



## सीएसआईआर-आईएमएमटी द्वारा बनाए गए वाटर फिल्टर का वितरण

भुवनेश्वर. भुवनेश्वर स्थित प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, सीएसआईआर-खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वारा विकसित टेराफिल पानी फिल्टर को गुरुवार पुरी जिले के अरहकुडा गाँव के लोगों में वितरण किया गया. सीएसआईआर-आईएमएमटी के निदेशक प्रो सुधास्वत बासु द्वारा माननीय की उपस्थिति में वितरित

किया गया है. अन्य अतिथियों के बीच ब्रह्मगिरी विधायक ललितेंदु विद्याधर महापात्र उपस्थित थे. निदेशक श्री बासु ने सभा को संबोधित किया और ओडिशा में संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी दी. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जे के पोथल और डी. सिंह ने पानी फिल्टर की उपयोगिता को समझाया और इसके संचालन का

प्रदर्शन किया. बता दे कि टेराफिल पानी फिल्टर एक कम लागत और टिकाऊ पानी फिल्टर हैं. यह फिल्टर मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी और रेत की धूल जैसी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों के मिश्रण से बना है. यह एक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्रकार फिल्टर है और इसके संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है.

**Published in:**  
Navbharat Times



CSIR-IMMT

20<sup>th</sup> September, 2019

## Distribution of “Terafil Water Filters” developed by CSIR-Institute of Minerals & Materials Technology, Bhubaneswar at Arakhakuda village of Puri district



Terafil water filter developed by one of the premier National R&D laboratory, CSIR- Institute of Minerals & Materials Technology, Bhubaneswar has been distributed to people of Arakhakuda village of Puri district by Director-CSIR-IMMT, Prof. Suddhasatwa Basu in presence of MLA, Brahamagiri, Lalitendu Bidyadhar Mohapatra on September 18, 2019. Director CSIR-IMMT addressed the gathering and informed about various societal interventions carried out by the Institute in Odisha. Senior Scientist Dr. J. K. Pothal & D. Singh explained the usefulness of the water filter and demonstrated its operation.

Terafil water filter is a low cost and sustainable water filter for efficient treatment of iron & turbidity from drinking water. The filter media is made from mixture of naturally available materials such as Pottery clay, River sand & saw dust. It is a gravity flow type filter and doesn't require electricity for its operation. It has a very long life cycle with minimal maintenance cost.

**Published in:**

New Indian Express



CSIR-IMMT

20<sup>th</sup> September, 2019

## ଅରଖକୁଦା ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରାଟରଫିଲ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଓ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ

ବ୍ରହ୍ମଗିରି (ଆପ୍): ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ  
ଲୁଙ୍କର ଅରଖକୁଦା ଗ୍ରାମରେ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ବିକାସିତ ଟେରାଫିଲ୍  
ଡ୍ରାଟର ଫିଲ୍ଡର ବୁଧବାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ  
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଓ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟିର  
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସୁଜସନ୍ତ ବସୁ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି  
ଡ୍ରାଟର ଫିଲ୍ଡର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଫାନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ  
ଜଳର ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ  
ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ଡର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।  
ଏହି ଡ୍ରାଟର ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଟି କ୍ୟାଣ୍ଟେଲ ମାଟି, କରତଗୁଣ୍ଠ  
ଏବଂ ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ  
ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁ କହିଛନ୍ତି । ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟିର  
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପୋଥାଳ ଏବଂ ଦେବବ୍ରତ ସିଂଙ୍କ କହିବା  
ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ  
ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାଟର ଫିଲ୍ଡର  
ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି କିମ୍ବା  
ଅତି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପରେ  
ଅରଖକୁଦା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ  
ବିଧାନସଭା ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ  
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ମଧୁସୂଦନ ଲେଙ୍କା,  
ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟିର ପିଆରଓ ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦିପ୍ତ ବେହେରା ଓ  
ରବିନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

**Published in:**

Pramey



## **‘Proper alliance can make Bamboo-nomics work’**

CSIR-NEERI

19<sup>th</sup> September, 2019

For ‘Bamboo-nomics’ to become a major force in the country’s economy, experts said that there needs to be increased collaboration between scientists and industry. A special seminar organized by CSIR-Neeri to mark Bamboo Day in the city saw various experts sharing their views on how sustainable utilization of bamboo can go forward by integrating environment, society and economy.

Hemant Purohit, chief scientist at Neeri’s Environmental Genomics Division, said that the priority should be on informing the public about change of status for bamboo under Indian laws. Purohit said, “Majority of them are not aware that bamboo now can be cultivated on private land and used for commercial production. The union government in 2017 removed it from provisions of the Forest Act opening up avenues for commercial use. Right from household goods to creating energy, bamboo can be used everywhere.

I believe a cooperative type of set-up is required to get maximum acreage under cultivation.” Avanish Srivastava, the event’s chief guest and director of CSIR-Advanced Materials and Process Research Institute (Bhopal), said that the key to success lies in making a marketable product. “Scientists may work on bamboo products and materials for years only to realize that the industry does not want it.

Hence, it is crucial to collaborate with the industry beforehand, understand their requirements and then work towards that product,” he said. Bamboo composite materials, metal foams etc are just some of the innovative products that Srivastava’s team is working on. With over 1,500 species of bamboos, it is important for the cultivator to know which one to plant. Karamjit Singh, former director of Biological Survey of India, said that this



problem can be approached in two ways. “The cultivator can study the climate and soil conditions and seek expert advice on which species of bamboo would be suited to it. The other way is to see which bamboo is required by the market and then work backwards to ensure that such conditions are created,” said Singh. He added that almost all bamboo species will grow in climatic conditions of Vidarbha. “Of course, some high altitude species won’t survive here, but otherwise it’s very sturdy and thrives without much water requirements. The first year of plantation is where care is needed; after that, it is pretty much self-sustaining,” said Singh.

**Published in:**  
[The Times of India](#)



CSIR-CDRI

19<sup>th</sup> September, 2019

# CDRI scientists to get NASI awards

PIONEER NEWS SERVICE ■ LUCKNOW

Two CDRI scientists have been nominated for the prestigious awards by National Academy of Sciences (NASI). Atul Goel will receive the NASI-RELIANCE Industries Platinum Jubilee Award-2019. Senior principal scientist of CDRI, Goel has been recognised for his significant contributions to application-oriented innovations in the area of developing new drugs and diagnostics. He will be honoured with a plaque and Rs 3 lakh in cash at the 89th Annual Session of NASI to be held at Hyderabad in December later this year.

Besides, principal scientist Ritu Trivedi has been chosen for Dr P Sheel Memorial Lecture Award-2019 (Young Women Award) from NASI. She was selected for this award for her research in the area of metabolic bone disorders, specifically on osteoporosis and osteoarthritis. She has



worked on several molecules derived from either natural resources or chemically synthesised for improvement of bone health. Out of these, a pure small molecule has shown promise as an anti-resorptive agent and is being prepared for clinical trials.

**Published in:**

The Pioneer



CSIR-CDRI

19<sup>th</sup> September, 2019

## सीडीआरआई के वैज्ञानिक डॉ. अतुल व डॉ. रितु को प्रतिष्ठित नासी के सम्मान

लखनऊ। सीडीआरआई के दो वैज्ञानिकों को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (नासी) के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। डॉ. अतुल गोयल को रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2019 और डॉ. रितु त्रिवेदी को डॉ. पी शील मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2019, युवा महिला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।



डॉ. रितु त्रिवेदी

सीएसआईआर, लखनऊ के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अतुल गोयल को व्यावहारिक अनुसंधान आधारित नई दवाओं और डायग्नोस्टिक्स के विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। उन्हें दिसंबर में हैदराबाद में नासी के 89वें वार्षिक सत्र में तीन लाख रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। डॉ. गोयल ने हड्डियों के फ्रैक्चर के तेजी से उपचार के लिए बायोडिग्रेडेबल मेडिकेटेड ऑर्थोबायोलॉजिकल, बोन इम्प्लांट्स विकसित किया। हैदराबाद स्थित एक कंपनी को इसकी तकनीक हस्तांतरण किया गया है। वहीं सीएसआईआर-सीडीआरआई की प्रधान वैज्ञानिक डॉ.



डॉ. अतुल गोयल

रितु त्रिवेदी को बोन मेटाबोलिक डिस्ऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए दिया गया है। उन्होंने हड्डियों की सेहत में सुधार के लिए प्राकृतिक स्रोतों एवं रसायनिक रूप से संश्लेषित कई यौगिकों पर काम किया है।

**Published in:**

Amar Ujala



# राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में मना हिन्दी पखवाड़ा

हैदराबाद, 18 सितंबर (स्वतंत्र वार्ता)। सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. वी.एम. तिवारी ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. कृष्ण देव शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान

भारत में विज्ञान लेखन की परंपरा, देश की भाषाई स्थिति, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार संबंधी इतिहास, समाज के उत्थान में भाषाओं का महत्व तथा संघ सरकार की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रासंगिकता आदि पर प्रकाश डाला। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिन्दी दिवस के अवसर पर दिए गए संदेश को संस्थान के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी चि.वै.सुब्बाराव ने पकर सुनाया। अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्थान के निदेशक डॉ. वी.एम. तिवारी ने कहा कि हिन्दी का कार्यान्वयन सिर्फ हिन्दी अनुभाग का काम नहीं है। सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर इस प्रयास में प्रतिभागिता करनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे हिन्दी कार्यशालाओं में अनिवार्य रूप से भाग लें। नियमित रूप से ग क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरेक कर्मचारी को भरसक प्रयास करना चाहिए। जिन नियमों, विनियमों के तहत शेष कार्य करने और वेतन लेने के लिए कर्मचारी बाध्य हैं उन्हीं नियमों व



विनियमों के तहत राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भी बाध्य हैं। उन्होंने अंत में पुरस्कार प्राप्त सभी कर्मचारियों को बधाई दिया। इस अवसर पर हिन्दी दिवस तथा पखवाड़ा आयोजन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के बारे में बताया और हिन्दी का इतिहास एवं विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने संस्थान की हिन्दी गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला।

संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक वाई. रामकृष्णा ने संसदीय राजभाषा समिति और उसके महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि संसदीय समिति के निरीक्षण में सूक्ष्म स्तर पर दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। अतः प्रशासनिक स्तरों में हिन्दी में टिप्पणी लेखन कार्य को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हिन्दी अनुभाग से मदद ली जा सकती है। उन्होंने अंत में कहा कि इस पंद्रह दिनों के भव्य समारोह के सफल आयोजन के लिए संस्थान का हिन्दी

अनुभाग बधाई का पात्र है। कार्यक्रम में संस्थान के कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली "हिन्दी में टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत विजेताओं को और हिन्दी पखवाड़े के

दौरान संस्थान के कर्मचारियों, शोध छात्रों तथा परियोजना स्टाफ के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी दर्शकों में से डू निकाल कर पाँच कर्मचारियों को चुनकर हिन्दी प्रेमी सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रीमती रुक्मिणी वेकेश्वरन, निजी सचिव द्वारा प्रस्तुत वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि का परिचय डॉ. प्रभा पांडेय, वैज्ञानिक ने दिया। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. डी. शशिधर द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।



CSIR-CRRI

19<sup>th</sup> September, 2019

## Airfield pavement management system in India for the first time

**ABBINAYA  
KUZHANTHAIVEL**  
NEW DELHI, SEPTEMBER 19

THE AIRPORTS Authority of India (AAI), along with the CSIR-Central Road Research Institute (CRRI), is set to install airfield pavement management systems (APMS), in a first, at 10 airports across India.

Chennai, Surat, Kolkata, Gaggal, Imphal, Agartala, Vadodara, Rajahmundry, Khajuraho and Gaya are the medium traffic airports short-listed for the APMS project. It will assist airport managers in developing viable strategies to maintain the pavements in a serviceable condition over a given period and quantify information on maintaining a pavement network at an acceptable level of service. It will also optimise pavement-related expenditure. The APMS will work in the concept of digitisation with scientific equipment. The CSIR-CRRI will assess the runways' functional and structural condition using state-of-the-art technology. Based on the survey parameters, the APMS system will function as a condition index, which will score the status as excellent or poor. The runways can be revamped or conditioned ensuring good maintenance.

Anil Kumar Pathak, member (planning), AAI, said, "The pavement is probably the most important airport asset. This is particularly the case for single-runway airports such as a majority of the Indian airports. It should be constructed and maintained at acceptable levels

**Chennai, Surat, Kolkata, Gaggal, Imphal, Agartala, Vadodara, Rajahmundry, Khajuraho and Gaya are the shortlisted medium traffic airports**

to meet international standards as pavements have a significant impact on airport users' cost, safety, traffic delay, commercial performance and reputation. Keeping in view the above facts, initially, 10 airports across the country are set to have the APMS."

Satish Chandra, director at CRRI (Council of Scientific & Industrial Research) said, "Around 10 airports in India will have APMS initially. (The) initiative... to tie up with the AAI for such an initiative (is happening) for the first time. We are planning to start once after the airport locations are confirmed."

"The AAI has decided to develop its maintenance plans. This will ensure the durability of the runways and ensure safe landing and take-offs," said Pradeep Kumar, senior principal scientist and head, pavement evaluation at CRRI-CSIR. Kumar added that a state-of-the-art network survey vehicle system, equipped with laser sensors, pavement surface imaging tools, GPS and structural condition data based on FWD equipment, will be used for health monitoring of the runway pavement network. "Various parameters

like runway pavement surface distress, profile, friction, pavement classification number, along with some health indicators, will be used to get the rating score to decide the maintenance strategies scientifically. Some medium traffic airports were shortlisted," said Kumar.

Pathak added: "Airfield pavements comprise multiple layers of engineered materials, such as asphalt, concrete and granular materials, designed to carry aircraft loading. Pavements deteriorate with time under loading and from environmental variations. Maintenance and rehabilitation are required to maintain serviceability throughout the pavement asset's life."

The project fieldwork is expected to start in October and will continue for three years. The budget has been set at Rs 4.5 crore. Pathak further added that as per prevalent practice, the full length of the pavement would be resurfaced after a certain period or in case of deterioration and with APMS, the weak portion could be identified well in advance to take up necessary rehabilitation or repair measures for that particular area.

With American and European countries having their own pavement management systems, India is not too late to start to ensure safety managements. Kumar added that the civil aviation ministry initiated the process. "The damages or faults in the pavements can be identified well in advance, which will help to avoid complete revamping of the pavement," said Kumar.

**Published in:**  
Indian Express



CSIR-IHBT

18<sup>th</sup> September, 2019

# फूल सुधारेंगे लेह-लद्दाख के किसानों की आर्थिकी सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्र में फूलों की खेती करेगा आईएचबीटी, लद्दाख की सोसायटी से करार

विनोद राणा

पालमपुर (कांगड़ा)। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बने लेह-लद्दाख के किसानों की आर्थिकी को फूल सुधारेंगे। लेह-लद्दाख में केसर सहित दमस्क गुलाब, कैमोमाइल, जंगली गेंदा, रोजमेरी, लैवेंडर और ड्रेकोसेफेलम फूलों की खेती होगी। वहां सीएसआईआर-आईएचबीटी पालमपुर सुगंधित फसलों की खेती करेगा। इन फूलों के लिए वहां की जमीन और जलवायु बेहतर पाई गई है।

लेह-लद्दाख में सुगंधित फूलों की खेती के लिए सीएसआईआर ने लेह और लद्दाख की फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड लद्दाख के साथ समझौता किया है। सिंचाई सुविधाओं से वंचित इस इलाके की उपयोगिता को बढ़ाने के



सीएसआईआर पालमपुर में लद्दाख सोसायटी और संस्थान के अधिकारी समझौता करते हुए

## 5500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा

आईएचबीटी के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन कार्यक्रम के तहत 5500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का निर्णय लिया। सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाई अनिवार्य है। लेह में इस सुविधा की स्थापना से लेह जिले के स्थानीय किसानों को लाभ होगा। सुगंधित फसलों से निकलने वाले तेल का उपयोग, कृषि, खाद्य स्वाद, दवाओं और इत्र जैसी चीजों में होता है।

लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएसआईआर और सोसायटी ने यह फैसला लिया है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित लद्दाख का क्षेत्र इस समय करीब 59.146 वर्ग किलोमीटर है। प्रयोग सफल रहा तो

आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों की तकदीर बदल जाएगी। खेती को बढ़ावा देने के लिए अगस्त माह में लेह के रणवीरपुरा गांव, में जागरूकता और प्रशिक्षण किसानों को दिया जा चुका है। यह देख लेह और लद्दाख के किसानों ने

सुगंधित फसलों के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

लिहाजा, अब सीएसआईआर और लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (एलएफपीसीएल) मिलकर इस काम को करेगी। वहीं किसानों को जंगली गेंदा, कैमोमाइल और केसर के बीज के साथ कृषि प्रौद्योगिकियों की पूरी जानकारी के पैकेज भी प्रदान किए गए। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि लेह और लद्दाख क्षेत्र उच्च मूल्य की सुगंधित फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है।

**Published in:**

Amar Ujala



## HC gives BBMP 10 days to entrust study of lakes to NEERI

CSIR-NEERI

18<sup>th</sup> September, 2019



**It has to pay for the study and execute agreement with the institute**

Observing that the State government has taken its own time to appoint CSIR-National Environmental Engineering Institute (NEERI) for an in-depth scientific study of lakes in the limits of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), the High Court of **Karnataka** on Tuesday set a 10-day deadline for the BBMP to pay the amount needed for the study and to execute the agreement with NEERI. A Division Bench comprising Chief Justice Abhay Shreeniwas Oka and Justice Mohammad Nawaz issued the direction after noticing that NEERI was

yet to be assigned with the task though the court had issued a direction in this regard in June. The Bench was hearing a PIL petition, filed in 2014 on the issue of lack of maintenance of stormwater drains (SWDs) and of lakes by preventing entry of sewage into SWDs, through which the court is monitoring actions of the civic bodies. Meanwhile, the bench declined the BBMP's request to continue development works in Begur lake, particularly the construction of three islands in the lake and the installing of a Shiva statue on one of the islands. It said that prima facie, permission granted to the BBMP by the authority constituted under the Karnataka Tank Conservation and Development Authority Act, 2014, was contrary to Section 12(2) of the Act which prohibits construction any structure on tank land, occupying of any tank land or part there of or causing any obstruction of the natural or normal course of inflow or outflow of water into, or from, the tanks. The authority had no power to grant such



permission as structures being put up are neither bridges, roads, or similar construction for which permission can be granted. Meanwhile, the State government informed the Court that it will take a decision on 19 'disappeared' lakes due to the diversion of lakes for other purposes after NEERI submits its report on the same. The court had earlier asked the government to decide to either restore or create artificial lakes to compensate for the loss of 19 lakes.

**Published in:**  
[The Hindu](#)



## CSIO develops targeting, navigation system for Navy

CSIR-CSIO

17<sup>th</sup> September, 2019

A mission critical navigation and targeting system for the Navy's warships and submarines has been developed by the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) here that would now be manufactured commercially. Christened Marine Bearing Sight (MBS), it provides instantaneous azimuth of identified targets, whether on shore or in sea, other vessels and even astronomical bodies. Azimuth is the horizontal direction expressed as the angular distance between the direction of a fixed point and the direction of the object.

The MBS is used in conjunction with the Marine Compass Repeater System onboard naval ships to provide an accurate means to indicate the true north and corresponding directions of ships, according to a statement issued by the CSIO here today. It is provided with in-built illumination for night operations. The device provides unique features of multiple focal lengths and all lighting conditions. The technology is an offshoot of the ongoing activities in the related fields and outcome of the recent memorandum of understanding between Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) and the Navy.

The technology was unveiled by Dr Shekhar C Mande, Director General (CSIR), in New Delhi today. He lauded the efforts of Dr Vinod Karar and his team for commercialising the product in a very short span to meet strategic needs. CSIO Director Prof RK Sinha emphasised that it had become essential to have a sustainable industry-academia-laboratory-end user ecosystem for sharing resources, faster translation of technologies into products and critical evaluation of the developed product to develop next generation variants.

**Published in:**  
[The Tribune](#)



## Four-day Vigyan Mela ends with great zeal

CSIR-AMPRI

17<sup>th</sup> September, 2019

The four-day eighth Bhopal Vigyan Mela, organised at BHEL Dussehra Ground, concluded on Monday with a grand closing ceremony. The Mela which was organised with an objective to make common man aware of science and technology innovation witnessed great footfall. Minister of Panchayat and Rural Development Kamleshwar Patel and Former Governor of Haryana Kaptan Singh Solanki were chief guest on this occasion. Speaking on this concluding ceremony Minister Kamleshwar Patel expressed happiness over the advancements in the science and technology field in the country. He said that Science is associated with every aspect of human life. Scientific developments are making our lives better.

Kaptan Singh Solanki said that India's recent progress in the field of science and technology make us feel proud and whole world convinced with it. He congratulated Bhopal Vigyan Mela organisers for the successful event. Different scientific talents associated with innovation and researches were also honoured during this ceremony. Minister Kamleshwar Patel and Former Governor Kaptan Singh Solanki presented appreciation letter to the persons associated with their unique and innovative research in the field of science and technology. The Bhopal Vigyan Mela was jointly organised by Vigyan Bharti Bhopal, CSIR-Ampri Bhopal, Vigyan Prasar New Delhi and All India Council for Technical Education. This year Bhopal Vigyan Mela presented different theme based pavilions like Technology Demonstration, Handicraft, Healthcare, Agri-Tech as well as pavilions related to the planning and progress of upcoming projects of the government.

**Published in:**  
[The Pioneer](#)



## आधी हुई थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत, लागत कम

प्रदूषण पर वैश्विक चिंता के बीच जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने विकसित की तकनीक

**जागरण विशेष**

विकास श्रीवास्तव • जमशेदपुर

थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल से पैदा होने वाला प्रदूषण देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का सबब है। प्रदूषण कम करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बीच जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल) के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है, जिससे थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत आधी हो जाएगी। कई देशों में इस तकनीक पर काम किया जा रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। चीन और जापान जैसे देशों ने भी शोध शुरू किया था, लेकिन बीस साल तक समय लगने और काफी खर्च करने के बाद शोध

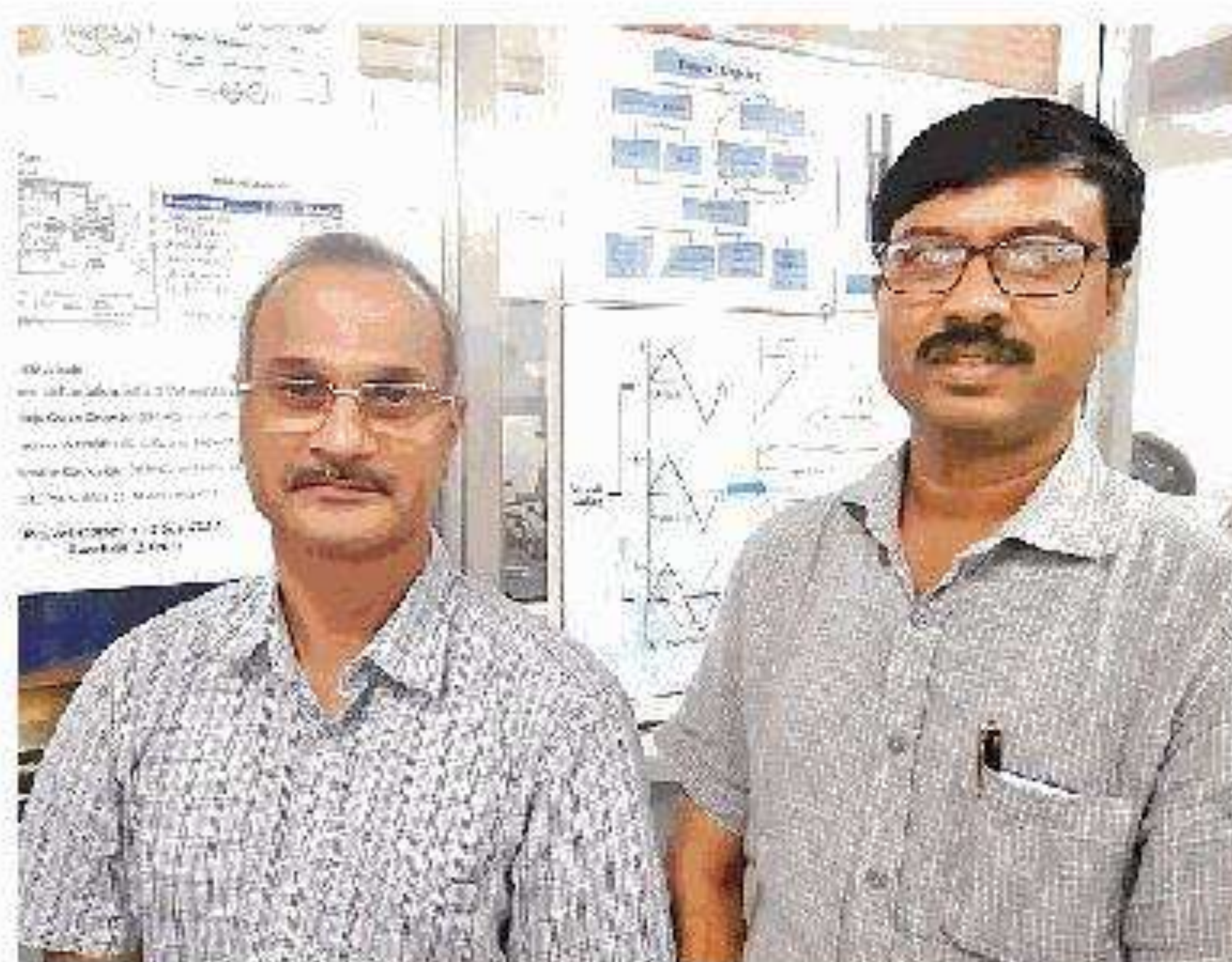
### बढ़ाया मान

- कोवले से पैदा होने वाले प्रदूषण से अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित
- चीन व जापान जैसे देशों ने भी किया था शोध, बाद में बंद किया

## नेशनल मिशन में शामिल

मैटैरियल इवैल्यूएशन फोर एडवांस्ड अल्टा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को भारत सरकार ने नेशनल मिशन प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नेशनल मिशन में इसके लिए भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड), एन्टीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) और आइजीसीएआर (इंदिरा गांधी सेंटर फोर एटॉमिक रिसर्च) को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है।

को बंद कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से जिम्मेदारी मिलाने के बाद एनएमएल जमशेदपुर



तकनीक विकसित करने वाली वैज्ञानिकों की टीम के लीडर डॉ. एस शिवप्रसाद (बाएं)। साथ में हैं सदस्य डॉ एचएन बार ● जागरण

## केंद्र सरकार की चिंता पर दिखाई गंभीरता

थर्मल पावर प्लांट में कोयले की अधिक खपत, अधिक कार्बन उत्सर्जन से प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की चिंता को एनएमएल के निदेशक डॉ. इंद्रनील चट्टोपायन ने गंभीरता से लिया। उनकी पहल पर एनएमएल के एमटीई (मैटीरियल इंजीनियरिंग डिवीजन) के वैज्ञानिकों ने तेजी से काम शुरू किया। टीम के लीडर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. एस शिव प्रसाद ने कहा कि हमारी टीम ने कोयले का विकल्प ढूंढने की जगह इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोयले से होनेवाले कार्बन उत्सर्जन को कम कर किस तरह प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके।

के वैज्ञानिकों ने इसका समाधान ढूँढने की कोशिश की, ताकि कोयले की खपत और कार्बन

रूखसर्जन को कम किया जा सके। दो साल की मेहनत के बाद कामयाबी मिली। इस तकनीक से कोयले

की खपत कम होने के कारण लागत के साथ-साथ अब प्रदूषण भी आधा हो गया।

## ऐसे मिली सफलता

थर्मल पावर प्लांट दरअसल, स्टीम (भाप) से चलता है। टरबाइन में भाप तैयार करने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। ज्यादा कोयले से पानी को गर्म कर भाप तैयार करने में ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। अध्ययन कर पावर प्लांट के उन खास बिंदुओं की पहचान की गई जहां कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सकता है और कम कोयले में भी वर्तमान उत्पादन संभव हो सकता है। इसके लिए कुछ नई तरह की धातुओं और मिश्र धातुओं को रिप्लेस किया गया। परिणाम सकारात्मक रहा। इस तकनीक को पहली बार झारखंड के पतरातू थर्मल पावर प्लांट में अपनाया जा रहा है। पतरातू में अपनाई जा रही तकनीक तमाम अध्ययन और शोध के बाद विकसित की गई है।



## NAL plans design, development of 70-seater aircraft

CSIR-NAL

16<sup>th</sup> September, 2019



BENGALURU: CSIR-National Aerospace Laboratories that is developing a 19-seater indigenous light transport aircraft 'Saras Mk2' has plans for a 70-seater aircraft, Union Science and Technology Minister Harsh Vardhan said on Monday. "Today itself they have started talking to me to get the permissions from and meetings with civil aviation ministry for their future plan of the 70-seater. That is also very heartening to know," Harsh Vardhan said. "Seventy-seater has always been in the long-term vision and since they have mentioned about this today we will have to bring the civil aviation ministry on board. We have to take the

approval of the Prime Minister's office. Also, we will have to take scientists also on board, so as a science and technology minister I will facilitate them to move in the right direction," he said. The Minister was speaking to reporters after laying the foundation for NAL's system check facility, aircraft integration facility, and the inauguration of smart aerospace composite manufacturing facility here. NAL director Jitendra J Jadhav said since NAL has a fair amount of experience, it would start the design of 70-seater. He said, "First, we will have to get in-principle approval from Ministry of Science and Technology, and Civil Aviation, also from Ministry of Finance, then we can finish design phase one-and-a-half year from that, which will be the preliminary design phase. Then we will submit it to the government, once the government sanctions, we will develop." CSIR-NAL is currently engaged in the design, development and certification of Saras Mk2, a twin-engine turboprop



19-seater transport aircraft for connecting small cities. Harsh Vardhan said everything was ready for the 19-seater, and the government has given all its support in terms of clearance and fund requirement to NAL. Expressing happiness that NAL was ready with a better advanced model and specification for the 19-seater, he said, "This 19-seater will be a boon for the people of the country, specially for improving and strengthening the regional travel or connectivity. Now we are in a stage that in the next few years, this 19-seater will be available for improving and strengthening the regional connectivity," he added. NAL officials said they have completed basic testing for pre-production standard. Jadhav said the first production of the 19-seater aircraft is likely by around 2025. "Four years for certification and and after that one-and-a-half year for production," he said. The officer said they were looking at civilian market of about 100 aircraft, adding that the Indian Air Force has committed to induct 15 such aircraft initially, and they may need another 45. He said the IAF version of Saras would be produced by HAL, and for civilian version also HAL may continue as production partner, but if demand is high, joint ventures may be worked out with private companies. The cost of the aircraft is likely to be at about Rs 45 crore and it was low compared to foreign aircraft may cost over Rs 70 crore. Regarding the two-seater Hansa-Next Generation aircraft, the production would start by 2022-23. Once the project starts its commercial operations, it would ease the availability of indigenous aircraft for pilot training to obtain private pilot and commercial pilot licenses, officials said. Regarding the cost of Hansa, Jadhav said NAL was looking for two versions, one basic and another deluxe. "Basic will be around Rs 1 crore, deluxe will cost about Rs 1.25 crore. For Hansa, flying clubs from across the country are potential customers, he said, adding that there may be requirement of over 200 aircraft as flying clubs are increasing. NAL had last year inked a pact with Delhi-based Mesco Aerospace Ltd for the design, development, production and marketing of the Hansa-Next Generation aircraft.

**Published in:**  
[Indian Express](#)



**Please Follow/Subscribe CSIR Social Media Handles**



[CSIR INDIA](#)



[CSIR\\_IND](#)



[CSIR India](#)